t o Rajya Sabha and Lok Sabha Secre ariats for construction of houses fortheir employees ;

(b) if so, when and where ;

(c)whether Government's acen-tion has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated the 15th March, 1992 captioned 'Governement staff face acute housing problems' ;

(d) if so, what is Government's reaction therero : and

(e) he progress made so far in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) No, Sir.

(b) In view of (a) above question does no: arise.

(c) Yes Sir.

id) and (e) During he Eighth Plan period he Government proposes o cons rue more flats in, he general pool for Central Government Employees. The progress in his regard would depend on he ex en of funds alloed for this purpose from year o year.

Action taken on CAG'S Report

2536. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Miniser of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state what action has been aken by Government on CAG's repon regarding use of over 80 per cem of sub-standard cons rue ion material by EDA for its ambiious Rohini scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M-ARUNACHALAM) : DDA have reported that samples are taken only in cases where preliminary investigations indicate possible substandard material/works.

As per CAG report, 366 samples were taken for testing but as per DDA records 264 samples were taken by the Quality Control Cell. Out of these 264 samples collected by the Quality Control Cell, 202 samples failed. Action taken for 202 samples is as under :—

(i) Material got removed work redone	41
(ii) Material accepted at reduced rates	144
(iii) Action in process	17
Total :	202

"हुडको" से उत्तर प्रदेश की आवासीय एजेंसियों को ऋण दिया जाना

2537. श्री ईश दत्त यादव : क्या कृपा शहरी विकास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की आवासीय एजेंसियां राज्य में आवासों के निर्माण और मूलभूत शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए 1990-91 में हुडको से ऋण प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्र श की आवासीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न ऋण प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय व राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, नहीं। वर्ष 1990–91 से और 30.6.1992 की स्थिति के अनुसार हुडको ने 3.67 लाख रिहायशी एककों और 1.34 लाख कम लागत के स्वच्छता एककों के निर्माणार्थ 651.02 करोड़ रुपये (शहरी अधंसंरचना के निमित्त 93.33 करोड़ रुपये सहित) की ऋण धनराशि वाली उत्तर प्रदेश की विभिन्न एजेंसियों की 386 स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(ख) और (ग) 8.7.92 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	स्कीम का प्रकार	स्कीमों की संख्या	हुडको ऋण धनराशि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1.	शहरी आवास स्कीमें	89	163.57	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए एजेंसियों के पास विचाराधीन।
2.	शहरी आवास स्कीमें	14	14.46	क्षेत्रीय तकनीकी समिति की मंजूरी की प्रतीक्षा।
3.	भूमि अधिग्रहण स्कीमें	14	78.94	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन।
4.	शहरी अधंसंरचना स्कीमें	2	13.20	हुडको के मुख्यालय में मूल्यांकनाधीन।
5.	–वही–	23	105.08	तकनीकी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन।
6.	वाणिज्यिक स्कीमें	2	5.93	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन।